

सशक्त जलवायु लक्ष्य 2030

प्रलिस के लयि:

जलवायु परविरतन, यूएनएफसीसीसी, सीओपी, पेरसि समझौता, राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान, अक्षय ऊर्जा, सरकारी पहल

मेन्स के लयि:

यूएनएफसीसीसी सीओपी, जलवायु परविरतन और इसके नहितारथ, जलवायु परविरतन से नपिटने के उपाय, सरकारी पहल ।

चर्चा में क्यो:

हाल ही में भारत ने वर्ष 2030 तक अपने जलवायु परविरतन लक्ष्यों में वृद्धिकी है ।

- वर्ष 2021 में ग्लासगो में [UNFCCC COP 26](#) में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से [जलवायु कार्रवाई](#) को सशक्त करने के लयि कई नए वादे कयि थे ।

भारत के संशोधति लक्ष्य:

परचिय:

उत्सर्जन तीव्रता:

- भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP की प्रतिइकाई उत्सर्जन\)](#) की [उत्सर्जन तीव्रता](#) में कम-से-कम 45% की कमी के लयि प्रतिबिद्ध है ।
- मौजूदा लक्ष्य **33% - 35% की कमी करना था** ।

वदियुत उत्पादन:

- भारत यह सुनिश्चति करने का भी वादा करता है कविवर्ष 2030 में स्थापतिवदियुत उत्पादन क्षमता का कम-से-कम **50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारति स्रोतों पर आधारति होगा** ।
- यह मौजूदा **40% के लक्ष्य से अधिक है** ।

महत्त्व:

- अद्यतन राष्ट्रीय रूप से नरिधारति योगदान (NDCs) [जलवायु परविरतन](#) के खतरे के प्रति वैश्वकि प्रतिकरिया को मज़बूत करने की दशा में भारत के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसा क [पेरसि समझौते](#) के तहत सहमत वियक्त की गई थी ।
- NDCs प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परविरतन के प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को शामिल करता है ।
- इस तरह की कार्रवाई से भारत को कम उत्सर्जन वृद्धिकी दशा में बढ़ने में भी मदद मलिंगी ।
- नए NDCs [ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन](#) से आर्थकि विकास को अलग करने के लयि उच्चतम स्तर पर भारत की प्रतिबिद्धता को प्रदर्शति करेंगे ।
- संशोधति NDCs के परिणामस्वरूप अकेले भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक [शुद्ध शून्य लक्ष्य](#) से उत्सर्जन में सालाना 60 मिलियन टन की कमी आएगी ।

अन्य NDCs:

- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW (गीगावाट) तक बढ़ाना ।
- वर्ष 2030 तक कुल अनुमानति कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन (BT) कम करना ।
- वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना ।

INDIA'S CLIMATE TARGETS: EXISTING AND NEW

Target (for 2030)	Existing: First NDC (2015)	New: Updated NDC (2022)	Progress
Emission intensity reduction	33-35 per cent from 2005 levels	45 per cent from 2005 levels	24 per cent reduction achieved in 2016 itself. Estimated to have reached 30 per cent
Share of non-fossil fuels in installed electricity capacity	40 per cent	50 per cent	41.5 per cent achieved by the end of June this year
Carbon sink	Creation of 2.5 to 3 billion tonnes of additional sink through afforestation	Same as earlier	Not clear.

जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास:

- **परविहन क्षेत्र में सुधार:**
 - भारत (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक) वाहन योजना को तेज़ी से अपना रहा है तथा वनरिमाण के साथ ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
 - पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिये **स्वच्छकि वाहन सुरैपगि नीति** भोजूदा योजनाओं की पूरक है।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में प्रोत्साहन:**
 - भारत उन गनि-चुने देशों में शामिल है जो वैश्वकि 'EV30@30 अभयान' का समर्थन करते हैं, जसिका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बकिरी में इलेक्ट्रिक वाहनों की हसिसेदारी को कम-से-कम 30% करना है।
 - ग्लासगो में आयोजति COP26 में जलवायु परिवर्तन शमन के लिये भारत द्वारा पाँच तत्त्वों (जसि 'पंचामृत' कहा गया है) की वकालत इसी दशिका में जताई गई परतबिदधता है।
- **सरकारी योजनाओं की भूमिका:**
 - **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** ने 88 मिलियन परिवारों को कोयला आधारति खाना पकाने के ईंधन से एलपीजी कनेक्शन में स्थानांतरति करने में मदद की है।
- **नमिन-कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका:**
 - भारत में सार्वजनिक और नजिकी क्षेत्र पहले से ही जलवायु चुनौती से नपिटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिरहे हैं, जहाँ ग्राहकों एवं नविशकों में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ बढ़ती नियामक तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं से सहायता मलि रही है।
- **हाइड्रोजन ऊर्जा मशिन:**
 - हरति ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रति करना।
- **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT):**
 - PAT ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये एक बाज़ार आधारति तंत्र है।

UNFCCC CoP26:

- **परचिय:**
 - संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ 26 को 2021 में ग्लासगो, यूके में आयोजति कयिा गया था।
- **बैठक का वविरण:**
 - **नए वैश्वकि और राष्ट्रीय लक्ष्य:**
 - ग्लासगो शखिर सम्मेलन ने वशिव के देशों से वर्ष 2022 में मसिर में आयोजति COP27 तक अपने वर्ष 2030 के लक्ष्य को और सशक्त बनाने पर वचिर करने का आग्रह कयिा।
 - शखिर सम्मेलन ने ग्लोबल वार्मगि को +1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देने का लक्ष्य रखा और लगभग 140 देशों ने अपने उत्सर्जन को 'शुद्ध शून्य' (NET ZERO) तक लाने हेतु अपनी लक्षति तथियिों की घोषणा की।
 - यह उपलब्धि महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पेरसि समझौते में वकिसशील देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिये सहमत नहीं हुए थे और उन्होंने केवल जीडीपी की 'उत्सर्जन-तीव्रता' को कम करने के प्रतसिहमति जताई थी।
 - भारत भी सर्वसम्मति से इसमें शामिल हो गया है और उसने **वर्ष 2070 के अपने नेट-ज़ीरो लक्ष्य की घोषणा की है।**
 - **ग्लासगो नरिणायक एजेंडा:**
 - ग्लासगो नरिणायक एजेंडा एक संभावति महत्त्वपूर्ण वकिस है जो CoP26 (लेकनि CoP प्रक्रयिा के अलग) से उभरा,

जैसे 42 देशों (भारत सहित) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- यह **स्वच्छ ऊर्जा**, सड़क परिवहन, इस्पात और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों एवं संधारणीय समाधानों में तीव्रता लाने के लिये एक सहकारी प्रयास है।
- **चरणबद्ध रूप से कोयले की खपत में कमी:**
 - **कोयला**, जीवाश्म ईंधनों में सबसे प्रदूषणकारी है, अतः ईंधन-स्रोतों के रूप में इसके प्रयोग को अत्यधिक कम करने की आवश्यकता है।
 - यूरोपीय देशों ने इसकी **खपत को कम करने** की पुरजोर वकालत की है; हालाँकि विकासशील देशों ने इसका वरिध किया है।
 - भारत ने CoP26 में एक मध्यम-मार्ग, अर्थात् कोयला आधारित बजिली उत्पादन में "चरणबद्ध रूप से कमी लाने" का सुझाव दिया है।
- **बेहतर परदृश्य:**
 - एक स्वतंत्र संगठन क्लाइमेट **एक्शन ट्रैकर (CAT)** द्वारा किये गए प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि घोषित लक्ष्य, अगर पूरी तरह से हासिल कर लिये जाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को लगभग +1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है।
 - हालाँकि यह चेतावनी भी जारी की गई है कि वर्ष 2030 के लक्ष्य अपर्याप्त रूप से महत्वाकांक्षी हैं। यदि किड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं तो वैश्विक स्तर पर तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस से 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मलि सकती है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. जलवायु अनुकूल कृषि के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- भारत में 'जलवायु-स्मार्ट ग्राम' दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (CCAFS) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।
- CCAFS परियोजना, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (CGIAR) के अधीन संचालित की जाती है जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।
- भारत में स्थिति अंतरराष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT), CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- भारत में जलवायु-स्मार्ट ग्राम परियोजना जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा (CCAFS) पर CGIAR अनुसंधान कार्यक्रम है। CCAFS ने वर्ष 2012 में अफ्रीका (बुरुकना फासो, घाना, माली, नाइजर, सेनेगल, केन्या, इथियोपिया, तंजानिया और युगांडा) तथा दक्षिण एशिया (बांग्लादेश, भारत, नेपाल) में जलवायु-स्मार्ट ग्राम का संचालन शुरू किया। **अतः कथन 1 सही है।**
- CCAFS की परियोजना अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह (CGIAR) के अधीन संचालित की जाती है। CGIAR का मुख्यालय मोंटपेलियर, फ्रांस में है। CGIAR वैश्विक साझेदारी है जो खाद्य सुरक्षा के बारे में अनुसंधान में लगे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को एकजुट करती है। **अतः कथन 2 सही है।**
- अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हेतु अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) CGIAR का अनुसंधान केंद्र है। ICRISAT गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में विकास के लिये कृषि अनुसंधान करता है, जिसमें दुनिया भर में भागीदारों की एक वसितृत शृंखला शामिल है। **अतः कथन 3 सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के वर्ल्ड लीडर्स समिटि में शुरू की गई ग्रीन ग्रिड पहल के उद्देश्य की व्याख्या कीजिये। यह विचार पहली बार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में कब लाया गया था? (मुख्य परीक्षा, 2021)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

